



Neutral Citation Number- 2026:AHC:31989

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या-5721/2026

दुखंती

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 10 अन्य

.....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता

: विनय कुमार सिंह

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., रामेश्वर प्रसाद शुक्ला

न्याय कक्ष संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी इस आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रत्यर्थी संख्या-2/ आयुक्त , आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़/अपर आयुक्त (प्रशासन), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़ को यह निर्देश दिया जाए कि वे पुनरीक्षण संख्या-120बी (कंप्यूटर वाद संख्या सी-202515000001363) (रामजनम बनाम दुखंती एवं अन्य) का शीघ्रता से निस्तारण करें।

4. यह मामला प्रत्यर्थी संख्या-2 के समक्ष काफी लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या-2/आयुक्त, आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़/अपर आयुक्त (प्रशासन), आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़, उपर्युक्त पुनरीक्षण पर कानून के पूर्णतः अनुरूप, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः अधीनस्थ अदालत के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर निर्णय लें; किंतु ऐसा करते समय, जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

12 फरवरी, 2026

सकलैन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”